भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
13.12.2023 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1669 का उत्तर

बड़ी रेललाइनों का विद्युतीकरण

1669. श्री जुएल ओराम:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की विभिन्न रेलवे जोनों में बड़ी लाइन के विद्युतीकरण की प्रगति के संबंध में कोई योजना है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और प्रगति क्या है;
(ग) सभी रेल जोनों में बड़ी लाइन के विद्युतीकरण को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और
(घ) सरकार द्वारा बड़ी लाइनों के विद्युतीकरण में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

s.k

बड़ी रेललाइनों के विद्युतीकरण के संबंध में दिनांक 13.12.2023 को लोक सभा में श्री जुएल ओराम के अतारांकित प्रश्न सं. 1669 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): जी, हां। भारतीय रेल की बड़ी लाइन (बीजी) के विद्युतीकरण में अब तक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अभी तक, नवंबर, 2023 तक भारतीय रेल की 60,814 किलोमीटर बड़ी आमान लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। इनमें से वर्ष 2004-14 के दौरान यह 5,188 किलोमीटर की तुलना में 2014 से नवम्बर 2023 तक के दौरान 39,013 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है।

(ग): विद्युतीकरण परियोजना (परियोजनाओं) का पूरा होना विभिन्न कारकों जैसे वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृतियां, बाधक जनोपयोगी सेवाओं की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृति स्थितियां, परियोजना (परियोजनाओं) स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए एक वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना (परियोजनाओं) के समापन समय को प्रभावित करते हैं। अतः परियोजना (परियोजनाओं) को पूरा करने के लिए इस समय कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(घ): रेल विद्युतीकरण कार्य में तेजी लाने के लिए, भारतीय रेल द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ; कमीशनिंग के दौरान बाधाओं के समाधान के लिए परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) पोर्टल का गठन, रेलवे बोर्ड स्तर पर परियोजनाओं के सुचारू और त्वरित अनुमोदन के लिए और प्रभावी परियोजना निगरानी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए रेलवे बोर्ड में 'गति शक्ति निदेशालय' का गठन शामिल हैं। इसके अलावा, परियोजनाओं के निष्पादन और पूरा करने में तेजी लाने के लिए बड़ी परियोजनाओं को 'इंजीनियरिंग संबंधी खरीद एवं निर्माण' (ईपीसी) संविदा मोड में निष्पादित किया जा रहा है, सुनिश्चित वित्त पोषण की व्यवस्था की जा रही है और फील्ड इकाइयों को वित्तीय शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया गया है।

*****

s.k